तेल कूटनीति का बदलता स्वरूप एवं ओपेक प्लस की महत्वपूर्ण भूमिका

*डॉ. हंसकुमार शर्मा

शोध सारांश

जब 20वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में अरब देशों में तेल की खोज व उत्पादन शुरू हुआ उक्त समय में पश्चिमी देशों व अमरीका की तेल कम्पनियों का वर्चस्व था। ये कम्पनियॉ तेल की कीमतों व उसके उत्पादन की मात्रा का निर्धारण पश्चिमी देशों के हितों को ध्यान में रखकर करती थी। इससे तेल उत्पादक देश व्यथित एवं परेशान थें। अतः तेल की कीमतों व उसके उत्पादन पर एक समन्यकारी नीति अपनाने के लिए तेल उत्पादक देशों ने 1960 में ओपेक (opec-organization of peterul Expurting Countries) की स्थापना की जिसके वर्तमान में 14 देश इसके सदस्य है। जिससे 5 देश ईरान, इराक, कुवैत, सउदी अरब तथा वेनेजुऐला इसके संस्थापक सदस्य है। अन्य 09 सदस्य देश–अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, लीबीया, नाइजीरिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इक्वेटारियल, गायना तथा गैबोन ओपेक के सदस्य मुख्यालय 'बगदाद' में था लेकिन वर्तमान में विएना में है।

ओपेक का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की तेल नीतियों में "समन्वय व एकीकरण करना जिससे अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर तेल उत्पादकों को तेल की उचित व स्थिर किमतें प्राप्त हो सके एवं तेल उपभोक्ताओं को समुचित कीमत पर स्थिर तेल आपूर्ति हो सकें तथा तेल उधोग में निदेशक कम्पनियों को उचित लाभ मिल सकें। उक्त सभी देशों में इस प्रकार ओपेक के तेल उत्पादक देशों, तेल उपभोक्ताओं तथा तेल उधोग में निवेशकों–तीनों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया था।

तेल राजनीति का बदलता हुआ स्वरूपः–

वर्तमान में विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में तेल के उत्पादन, कीमतों व बाजारों को लेकर जो तेल कूटनीति चल रही थी, वह नयी नहीं रही है बल्कि तेल कूटनीति आधुनिक अर्थव्यवस्था, परिवहन तथा प्रतिरक्षा में तेल की उपयोगिता व तेल संसाधनों के विश्व के असमान वितरण में निहित है। तेल संसाधनों के बिना आधुनिक विकास की कल्पना करना व्यर्थ था इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रतिरक्षा के उपकरणों यथा टैंक, लडाकू विमानों एवं आवागमन हेतु वाहनों की उपयोगिता के कारण बहुमूल्य संसाधन बन गया। इसमें 1859 में अमेरिका के पेनसिल्वानिया में सर्वप्रथम खोज रही लेकिन विश्व स्तर पर आपूर्ति के लिए प्र्याप्त नहीं थी, 1908 में पश्चिम एशिया में ईरान में पहली बार तेल की खोज हुई उसके बाद मध्यपूर्व के अन्य देशों में तेल के पर्याप्त भण्डार एवं 1938 में सउदी अरब में तेल का पता चला। लेकिन इन देशों के पास तेल के बहुमूल्य संसाधन के खोज, उत्पादन करने, उसको साफ सफाई एवं मरम्मत हेतु पर्याप्त वित्तीय एवं तकनीकी साधनों का अभाव था। अतः अमेरिका एवं यूरोपीय

देशों की तेल कम्पनियों ने इन तेल संसाधनों को अपने नियन्त्रण में (कब्जा) कर लिया। इनमें 07 कम्पनिया प्रमुख थी–1. स्टैण्डर्ड आयल, रॉयल डच अथवा शैल, बी.पी., मोबाईल, टैक्सिको, गल्फ तथा शैवर्न इन सात प्रमुख कम्पनियों का ही मध्य पूर्व तेल का उत्पादन व आपूर्ति पर अधिकार था इन्हें 'सेविन सिस्टर्स' के नाम से जाना जाता है।

तेल संसाधनों पर राष्ट्रीय नियन्त्रण की कूटनीतिः–

द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व औपनिवेशिक महत्ता जो विस्तारवादी नीति ने अमरीका एवं ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देशों ने अनोपचारिक साझा के तहत मध्यपूर्व के तेल उत्पादक क्षेत्रों का अपने–अपने प्रभाव क्षेत्र में मान लिया थ लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद (1941–1945) अरब देशों में 'राष्ट्रवाद' की भावनाओं का तेजी से विकास हुआ सर्वप्रथम 1956 में जब मिश्र ने 'स्वेज नहर' का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके पश्चात् ब्रिटेन व फ्रांस दोनों के लिए तेल की आपूर्ति मंहगी हो गई इजरायल के साथ मिलकर मिश्र पर आक्रमण करके अन्य अरब के देशों में अपने तेल संसाधनों का बाहरी कम्पनियों में अपने नियन्त्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, 1960 से ओपेक की स्थापना हुई उसी दिशा में एक प्रयास था। अगले दो दशकों तक के अरब देशों के तेल संसाधनों पर उनकी राष्ट्रीय कम्पनियों का अधिकार कायम हो गया।

तेल का एक राजनीति साधन के रूप में प्रयुक्त करने वाली कूटनीतिः–

अरब–इजरायल समस्या अरब देशों की एक प्रमुख समस्या थी यहूदी होने के कारण 1967 से पश्चिम देशों की सैन्य व आर्थिक सहायता से इजरायल के हाथो अरब देशों की पराजय जिससे अरब देशों के भू–क्षेत्रों यथा मिश्र का सिनाई प्रायद्वीप, सीरिया की गोलन पहाडियॉ तथा फिलिस्तीन का गाजा पट्टी क्षेत्र आदि पर इजरायल का कब्जा कर लिया एवं अरब देशों मे पश्चिम विरोधी–राष्ट्रवाद की भावना चरम पर पहुॅच गई। इसी पृष्ठभूमि में 1973 में चौथा अरब इजरायल युद्ध लेकिन परिस्थितियों ने कूटनीति द्वारा 'जो देश इस युद्ध में इजरायल का साथ देगें उनको तेल की आपूर्ति नहीं की जायेगी' जिससे अमेरिका तथा पश्चिम देशों में अरब देशों पर तेल की निर्भरता थी जिसका अकाल पड गया एवं आपूर्ति बन्द कर दी गई।

यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेल का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयाग का पहला उदाहरण था। कई समीक्षक इसे तेल कूटनीति की शुरूआत कहते है।

ओपेक प्लस क्या हैः–

तेल की खोज अन्य देशों में भी हुई लेकिन वे देश ओपके के सदस्य नहीं बने ऐसे गैर ओपेक देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए नया मंच का गठन किया गया है जिसे ओपके प्लस के नाम से जाना जाता है, 14 देशों के अतिरिक्त 10 अन्य देश उत्पादक देश शामिल है–रूस, ब्राजील, मैक्सिको, सूडान, ओमान, मलेशिया, अजरबेजान, बहरीन, बुनेई, कजाकिस्तान तथा दक्षिण सूडान तेल उत्पादन की कोष तथा नीति निर्धारण, किमतों में जो परिवर्तन का संकट आया है उसका प्रमुख कारण रूस व सउदी अरब के बीच उत्पादन कोटा में कमी व कार्य पर होने वाला विवाद है।

समकालीन तेल कूटनीति उत्पादक देशों के बीच बाजारों की प्रतिभोगिताः–

गत दशकों में तेल कूटनीति के संदर्भ में कई ऐसे बदलाव है जिनका निष्कर्ष एक तरफ तेल के उत्पादन में वृद्धि तथा दूसरी तरफ आशानुरूप पूर्व की भाँति तेल की खपत में कमी होना है। इसके मुख्य तीन कारण हैः–

प्रथमः– 2015 के पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अन्तर्गत 'स्वच्छ उर्जा के स्त्रोत का लक्ष्य' निर्धारित जिसमें कार्बन उत्सर्जन स्त्रोत जिसे तेल व कोयला के उपयोग में कटौती, चीन–भारत विश्व के दूसरे व तीसरे तेल की खपत करने वाले देश में भारत 2030 एवं चीन 2050 में स्वच्छ उर्जा स्त्रोत के खपत 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है एवं अन्य देशो में भी पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत बढाने की सम्भावना नहीं है।

द्वितीयः– दो दशक से ओपके का बर्चस्व खत्म हो गया वर्तमान में 39 प्रतिशत, ओपेक के एकाधिकार में कमी रही है एवं ओपेक प्लस के 10 गैर सदस्य विश्व तेल उत्पादन में 22 प्रतिशत है जिनमें रूस, ब्राजील, मैक्सिको आदि प्रमुख है। बहुत से देशों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीति कूटनीति के कारण, अरब, रूस, मिश्र, इजरायल, ईरान, अमेरिका, चीन व कोरिया की आर्थिक भूमण्डलीकरण राजनीति में एक ध्रुवियकरण अमेरिका में तेल उत्पादन की मात्रा में असहमति के कारण भी तेल में अभूतपूर्व गिरावट का प्रदर्शन रहा है वर्तमान में सऊदी अरब व रूस दूसरे व तीसरे स्थान पर उत्पादक देश है।

तृतीयः– 21वीं शताब्दी के पहले दशक तक में अमरीका व अन्य यूरोपीय देश अपनी आवश्यकता के लिए खाडी देशों से तेल के आयात पर निर्भर था, लेकिन मानवाधिकार तथा लोक तंत्र में खराब रिकार्ड के बावजूद सउदी अरब के साथ सामरिक सम्बन्धों का विकास, 1979 से 1985 में ईरान के शाह का समर्थन, कैम्प डेविड समझौते के आधार पर अरब एकता का विखण्डन का प्रयास, 1991 में प्रथम खाडी युद्ध ईराक के विरूद्ध आक्रमण, 2003 में ईराक के विरूद्ध सैनिक हस्तक्षेप, 2012 में लीबिया के सैनिक हस्तक्षेप एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 2001 से 2015 तक तालिबान, एशिया महाद्वीप में बहुत सी घटनाऐं चीन का चारा–छडीनीति, रूस का विखण्डन, यूरों का विकास, आतंकवाद, वारसा एक्ट का अंत, नाटों का विकास व विस्तार, यू.एन.ओ. द्वारा अमेरिका व पश्चिम देशों द्वारा वर्ष 2014 में '**शैल तकनीकी**' के आधार पर अमरीका विश्व का तेल उत्पादक बडा राष्ट्र जिसकी 22 प्रतिशत हिस्सेदारी होना, जिसके लिए विश्व के बाजार की तलाश कर रहा है। ईरान के विरूद्ध प्रतिबन्ध लगाना जबकि भारत 10 प्रतिशत तेल ईरान से आयात करता है, प्रतिबन्धों के बाद अमेरिका से आयात करना प्रारम्भ कर दिया, यूरोप के अन्य देशों में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। चीन का '**दक्षिण सागर**' में विस्तारवादी नीति वैश्विक हिन्द–प्रशन्त नीति का एक पहलू, हालांकि तेल व गैस की किमतों में भारी उतार व चढाव से वैश्विक मुद्रा अवमूल्यन व सूचकांक में असमानता से बाह्य स्त्रोतों पर निर्भरता में भारत को अपनी 83 प्रतिशत तेल आवश्यकताओं के लिए बाह्य स्त्रोत पर निर्भर है जिसमें दक्षिण एशिया में भारत को लाभ है लेकिन चीन की अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति में विस्तारवादी 'कर्जवादी नीति' से उर्जा के एक आवश्यक साधन के रूप में तेल का भविष्य एवं उत्पादकता में कटौती हेतु असहमति मंदी के दौर में अपने तेल के लिए अधिक से अधिक बाजारों को सुरक्षित करना था तेल की मॉग के अनुपात में तेल के अधिक उत्पादक होने की प्रत्याशा पर डालर प्रति बैरल से 35–30 डालर होने की आशंका मंदी को एक दशक तक चलने की आंशका है। उक्त में भारत एवं विकासशिल देश उर्जा के नये स्त्रोत द्वारा उक्त समस्याओं से समाधान प्राप्त कर सकते है जिसके लिए गैर परम्परागत स्त्रोत से उर्जा का विकास आवश्यक है। तथा डालर का विदेशी मुद्रा भण्डार नीजी क्षेत्र की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हस्तक्षेप, चीन की सामरिक नीति, अमेरिका बाजार में तेल की पहुॅच हेतु वैश्विक नीति से अन्तराष्ट्रीय राजनीति में तेल कूटनीति का बाजार विस्तारवादी नीति में राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप 'राष्ट्रवाद' की परिकल्पना से मुकदर्शक व असहाय में नयी समस्याओं को जन्म देगा जो विश्व राजनीति के लिए प्रतिद्वन्द्विता का नया रूप धारण करेगा।

सारांशतः–

20वीं शताब्दी में तेल कूटनीति तेल की सुरक्षा के लक्ष्य से प्रेरित थी वहीं 21वीं शताब्दी में इसका लक्ष्य उत्पादक देशों द्वारा विश्व के तेल बाजारों पर कब्जा करना है। इस कूटनीति के अब रूस व सऊदी अरब के साथ अमरीका

भी तेल उत्पादकता के रूप में शामिल हो गया है। जिसमें अरब देशों के वर्चस्व समिति में ओपेक प्लस ने महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रही है। वर्तमान में अरब (खाडी) देशों के वर्चस्व नीति में ओपके प्लस ने महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में नयी तेल कूटनीति विश्व व्यापार में स्थापित की है।

***प्राचार्य**
श्री वीर तेजाजी महाविधालय,
राडावास (जयपुर)

संदर्भ ग्रन्थः–

1. डॉ. कुलदीप फडीयाः– अन्तर्राप्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य प्रमुख संगठन, साहित्य भवन, सिकन्दराबाद, आगरा उत्तर प्रदेश, 2015
2. डॉ. बी.एल. फडीयाः– अन्तराप्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन, आगरा ;उत्तर प्रदेश, 2012
3. दैनिक समाचार पत्र (सम्बन्ध लेख)
4. डॉ. अशोक कुमारः उपकार प्रकाशन, आगरा, 2015